जनसत्ता 22 जुलाई 2017

शिक्षाविदों की अपील, शिक्षा बजट बढ़ाया जाए

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 जुलाई।

देश के कई शिक्षाविदों का मानना है कि स्कूली शिक्षा के लिए वित्तीय संसाधनों की पर्याप्तता की कमी है। इसे न केवल बढ़ाया जाना चाहिए बल्कि राज्यों को और संवेदनशील बनाया जाना चाहिए, नहीं तो शिक्षा का अधिकार कानून अपने मूल उद्देश्यों को पाने में पिछड़ता जाएगा।

राइट टु एजुकेशन फोरम की अगुआई में देश में स्कूली शिक्षा के लिए वित्तीय संसाधनों की पर्याप्तता पर शुक्रवार को दिल्ली में मंथन करने वालों में एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक प्रो कृष्ण कुमार, पूर्व विदेश सचिव मुकुंद दूबे, जेएनयू के प्रोफेसर प्रवीन झा, पूर्व कुलपति (एनयूईपीए) व सीएसडी के प्रो आर गोविंद, दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रो पूनम बत्रा के अलावा गैर-सरकारी संगठन क्राई के शोधार्थी सहित देश के 16 राज्यों से आए शिक्षण प्रतिनिधि शामिल थे। चर्चा का केंद्र शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6 फीसद खर्च करने की पचास साल पहले आई कोठारी आयोग की सिफारिश का अब तक लागू न हो पाना था। चर्चा का मसौदा फोरम के अमरीश राय ने रखा।